



2026:AHC:67270

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 6707 वर्ष 2026

उप-निरीक्षक लालबहादुर प्रसाद आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: रघुवंश मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 73

माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

1. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रघुवंश मिश्रा को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मुकदमा चलाया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार आरोप यह है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 5000/- रुपये की मांग की है। आवेदक एक उपनिरीक्षक है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिकी के अवलोकन से पता चलता है कि एकमात्र आरोप यह है कि 5000/- रुपये की मांग की गई है, हालांकि, रिश्वत के रूप में राशि स्वीकार नहीं की गई है। आवेदक के अधिवक्ता ने **नीरज दत्ता बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), (2023) 4 एस.सी.सी. 731** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के प्रस्तर-88 पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत आरोपी लोक सेवक के अपराध को स्थापित करने के लिए मांग का प्रमाण और साथ ही एक लोक सेवक द्वारा अवैध संतुष्टि की स्वीकृति एक अनिवार्य शर्त है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्वीकृति के प्रमाण के संबंध में अभिलेखों पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है और इस तरह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 का प्रावधान प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आकर्षित नहीं होगा। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 24.11.2025 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

3. राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आरोप के अनुसार आवेदक सूचनाकर्ता के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 5000/- रुपये की मांग कर रहा था, हालांकि, इस तथ्य पर विवाद नहीं करता है कि प्रस्तुत मामले में रिश्वत की कोई स्वीकृति नहीं है और केवल मांग की गई थी।

4. राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के आपराधिक इतिहास या पूर्ववृत्त को इंगित करने के लिए कोई तथ्य या परिस्थितियां नहीं लाए हैं जो आवेदक को जमानत के लिए अपात्र बना देगा।

5. यह राज्य का मामला नहीं है कि आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष जांच या कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है। राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दिखाई है जो आवेदक को जमानत से इनकार कर देगी।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा राज्य के लिए कोई सामग्री, तथ्य या परिस्थितियां नहीं दिखाई गई हैं कि अभियुक्त सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या अभियुक्त इस तरह का चरित्र का है कि बड़े पैमाने पर उसकी उपस्थिति मात्र गवाहों को डरा देगी या अभियुक्त न्याय को नष्ट करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा।

7. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक के न्याय से भागने या न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने या अपराधों को दोहराने या गवाहों को डराने आदि के रूप में अन्य परेशानी पैदा करने का कोई भौतिक विवरण या परिस्थितियां नहीं दिखाई गई हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. यह देखा जाना चाहिए कि नीरज दत्ता (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के प्रस्तर-88 में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। प्रस्तर-88 को यहां नीचे उद्धृत किया गया है: -

"88. उपरोक्त चर्चा से जो निकलता है उसका सारांश निम्नानुसार है:

88.1. (ए) अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत आरोपी लोक सेवक के अपराध को स्थापित करने के लिए अभियोजन द्वारा जारी एक तथ्य के रूप में एक लोक सेवक द्वारा अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति का प्रमाण अनिवार्य शर्त है।

88.2. (बी) अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले अवैध संतुष्टि की मांग और बाद में तथ्य की बात के रूप में स्वीकृति को साबित करना होगा। इस मुद्दे में इस तथ्य को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है जो मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य की प्रकृति में हो सकता है।

88.3. (ग) इसके अलावा, इस मुद्दे में तथ्य, अर्थात्, अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति का प्रमाण प्रत्यक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है।

88.4 (घ) मुद्दे में तथ्य को साबित करने के लिए, अर्थात्, लोक सेवक द्वारा अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति, निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना होगा:

(i) यदि लोक सेवक से कोई मांग किए बिना रिश्वत देने वाले द्वारा भुगतान करने का प्रस्ताव है और बाद वाला केवल प्रस्ताव स्वीकार करता है और अवैध संतुष्टि प्राप्त करता है, तो यह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्वीकृति का मामला है। ऐसे मामले में, लोक सेवक द्वारा पूर्व मांग की आवश्यकता नहीं है।

(ii) दूसरी ओर, यदि लोक सेवक कोई मांग करता है और रिश्वत देने वाला मांग को स्वीकार करता है और मांगी गई संतुष्टि की निविदा करता है जो



बदले में लोक सेवक द्वारा प्राप्त होता है, तो यह प्राप्ति का मामला है। प्राप्ति के मामले में, लोक सेवक से अवैध परितोषण की पूर्व मांग निकलती है। यह अधिनियम की धारा 13(1)(d)(i) और (ii) के तहत अपराध है।

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) दोनों मामलों में, रिश्वत देने वाले द्वारा की गई पेशकश और लोक सेवक द्वारा की गई मांग को क्रमशः अभियोजन पक्ष द्वारा एक तथ्य के रूप में साबित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल कुछ भी बिना किसी अन्य चीज के अवैध संतुष्टि की स्वीकृति या प्राप्ति इसे अधिनियम की धारा 7 या धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत अपराध नहीं बनाएगी। इसलिए, अधिनियम की धारा 7 के तहत, अपराध को घर लाने के लिए, रिश्वत देने वाले से निकलने वाला एक प्रस्ताव होना चाहिए जिसे लोक सेवक द्वारा स्वीकार किया जाता है जो इसे अपराध बना देगा। इसी तरह, लोक सेवक द्वारा पूर्व मांग जब रिश्वत देने वाले द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और बदले में लोक सेवक द्वारा प्राप्त किया गया भुगतान होता है, तो अधिनियम की धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत प्राप्ति का अपराध होगा।

88.5 (ई) अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति या प्राप्ति के संबंध में तथ्य की धारणा कानून की अदालत द्वारा एक अनुमान के माध्यम से केवल तभी की जा सकती है जब मूलभूत तथ्य प्रासंगिक मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किए गए हों और उसके अभाव में नहीं। अभिलेखों पर सामग्री के आधार पर, न्यायालय के पास तथ्य की धारणा बनाने का विवेक है, जबकि यह विचार करते हुए कि मांग का तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है या नहीं। बेशक, तथ्य की एक धारणा अभियुक्त द्वारा खंडन के अधीन है और खंडन अनुमान के अभाव में खड़ा है।

88.6 (च) यदि शिकायतकर्ता 'शत्रुतापूर्ण' हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो गई है या मुकदमे के दौरान अपने साक्ष्य को देने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो किसी अन्य गवाह के साक्ष्य को स्वीकार करके अवैध संतुष्टि की मांग को साबित किया जा सकता है, जो फिर से मौखिक रूप से या दस्तावेजी साक्ष्य



द्वारा साक्ष्य दे सकता है या अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा मामले को साबित कर सकता है। मुकदमे में कमी नहीं आती है और न ही इसके परिणामस्वरूप आरोपी लोक सेवक को बरी करने का आदेश दिया जाता है।

88.7 (छ) जहां तक अधिनियम की धारा 7 का संबंध है, मुद्दे में तथ्यों के प्रमाण पर, धारा 20 अदालत को यह अनुमान लगाने के लिए बाध्य करती है कि अवैध संतुष्टि उक्त धारा में उल्लिखित उद्देश्य या इनाम के उद्देश्य से थी। उक्त अनुमान को अदालत द्वारा कानूनी अनुमान या कानून में एक अनुमान के रूप में उठाया जाना चाहिए। बेशक, उक्त अनुमान भी खंडन के अधीन है। धारा 20 अधिनियम की धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) पर लागू नहीं होती है।

88.8 (ज) हम स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 20 के तहत कानून में अनुमान उपरोक्त उप प्रस्तर-88.5 (ई) में ऊपर उल्लिखित तथ्य की धारणा से अलग है, क्योंकि पूर्व एक अनिवार्य अनुमान है जबकि बाद वाला प्रकृति में विवेकाधीन है।

9. नीरज दत्ता (उपरोक्त) मामले में निर्णय के प्रस्तर-88.1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून में आवश्यक तत्वों में से एक के लिए आवश्यक है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति का प्रमाण अनिवार्य शर्त है।

10. एक बार जब यह प्रतिपक्षी का एक स्वीकृत मामला है कि आवेदक द्वारा कोई अवैध संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी और जब तक अवैध संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत शर्त पूरी नहीं की जा सकती है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला नीरज दत्ता (उपरोक्त) मामले में निर्धारित कानून के अनुसार नहीं हो सकता है।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, पक्षों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ, इस तथ्य के साथ कि आवेदक का कोई



आपराधिक इतिहास नहीं है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की **अनुमति** है। प्रस्तुत मामले में की गई टिप्पणियों से मामले की सुनवाई किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी।

12. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अपराध संख्या-441 वर्ष 2025 में शामिल आवेदक-उपनिरीक्षक लालबहादुर प्रसाद, थाना-देवगांव, जिला आजमगढ़ को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि में दो-दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए: -

- i. आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।
- iii. आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं दी जाती है और/या आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा।
- iv. आवेदक उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिसके बारे में उस पर आरोप लगाया गया है, या उस पर संदेह है, जिसके बारे में उस पर संदेह है।
- v. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
- vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- vii. यदि आवेदक आवासीय पता बदलता है, तो आवेदक संबंधित अदालत को नए आवासीय पते के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।



13. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 31, 2026

वीएमए

(विक्रम डी. चौहान)

Translated Version. Not for Legal Use.